साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 05 जनवरी से 11 जनवरी 2025
हम दिखाएंगे आईना...
वर्ष : 01 अंक : 44 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 08 में...
170 दिन बाद चैतन्य की 'घर वापसी'

पेज 12 में...
करोड़ों का 'वन भैंसा' घोटाला

पेज 03 **बिजली का 'शॉक' लगने की तैयारी**

टाप गियर में साय सरकार...

महज दो साल में आधा दर्जन कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

जनहित, विकास, आधुनिकीकरण के लिए सरकार के पास कई योजनाएं

18 लाख आवास, महिलाओं को मिले 14 हजार करोड़, 32 हजार पदों पर भर्ती जारी

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

साय सरकार के दो साल पूरे हो गए। सरकार की उपलब्धियां और कार्यशैली अब पूरी रफ़्तार में है। रायपुर में सीएम साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा सात कैबिनेट मंत्री भी अब पूरी गंभीरता से काम में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के दूसरे दिन ही 18.12 लाख जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास उपलब्ध कराने का फैसला सर-अंजाम दिया गए है। सीएम ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे अपितु छत्तीसगढ़ के विकास, आधुनिकीकरण, नक्सलमुक्त राज्य और लोकहित के साथ युवाओं के लिए रोजगार परक योजनाओं को अकार देने में लगे हैं।

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। राज्य में अब तक 505 नक्सली मारे गए हैं. वहीं, 2386 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण - किया है. इसके अलावा 1901 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं. नक्सलवाद इलाकों में 69 सुरक्षा कैंप स्थापित हो चुके हैं। नक्सवाद को खत्म करने में नई पुनर्वास नीति नियद नेल्ला नार योजना भी बहुत कार्यकारी रही है। इस नीति से प्रभावित होकर नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. नक्सल हिंसा के कारण बंद हुए 50 स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। अब असपताल भी खुल रहे हैं। नक्सल प्रभावित 403 गांवों में 53 सरकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है. यहां पक्की सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, मोबाइल टावर, राशन दुकान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति बनाई है। भारी संख्या में आत्म समर्पित करने वाले नक्सलियों को तीन साल तक दस हजार रुपये महीने देने का प्रावधान है।

कृषक उन्नति योजना

- किसानों की आमदनी बढ़ाना, कृषि लागत में राहत देना, फसल विविधीकरण व उन्नत तकनीक प्रोत्साहन
- बजट (2025-26): ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- धान का मूल्यः ₹3100 प्रति क्विंटल (समर्थन मूल्य + अंतर की राशि)। खरीद सीमाः प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीद।
- अंतर राशि का भुगतानः धान के मूल्य की ₹12 हजार करोड़ की अंतर राशि का किसानों को एकमुश्त भुगतान।
- अनुदान (2025-26): धान कॉमन के लिए ₹15,351 प्रति एकड़ और धान (ग्रेड-ए) के लिए ₹14,931 प्रति एकड़ अनुदान।
- अब रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसान भी लाभान्वित होंगे, इसमें बीज एवं कृषि विकास निगम/सहकारी समिति को धान बेचने वाले किसान भी शामिल हैं।
- अन्य फसलों के लिए आदान सहायताः दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ की आदान सहायता।
- धान के पंजीकृत रकबे में अन्य फसल की खेती करने पर ₹11,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी।

सुशासन से समृद्ध छत्तीसगढ़

- सुशासन यानी अंत्योदय का मंत्र
- छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी व जवाबदेह शासन
- पिछले 22 महीनों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
- मोदी की गारंटी और जनकल्याणकारी योजनाओं का तेज़ क्रियान्वयन
- ई-गवर्नेस से योजनाओं की निगरानी, जनता का पैसा केवल जनता के हित के लिए अब तक 350+ सुधार (रिफार्म) लागू
- सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना, सुशासन हर स्तर पर लागू
- ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य में दक्षता, जवाबदेही और समय की बचत
- 266 करोड़ रुपए के आईटी टूल्स से विभागीय गतिविधियों में पारदर्शिता और लीकेज पर रोक

प्रधानमंत्री आवास योजना

- प्रदेश में अब तक 26 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की दी जा चुकी है स्वीकृति।
- आवास प्लास 2.0 के सर्वेक्षण द्वारा राज्य को 10 लाख अतिरिक्त आवास प्राप्त होंगे।
- प्राप्त 14.5 लाख आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध 12.57 लाख आवास स्वीकृत कर कुल 8948.68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47,090 परिवार होंगे पीएम आवास योजना से लाभान्वित।
- राज्य में पीएम आवास योजना ग्रामीण में 3.03 लाख नए आवास स्वीकृति।
- वर्ष 2025-26 में पीएम आवास ग्रामीण हेतु 8500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान।

शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

- लगभग 15,165 शिक्षकों का समायोजन आवश्यकता वाले स्कूलों में किया गया।
- राज्य के सभी 453 शिक्षक-विहीन विद्यालयों में अब शिक्षक पदस्थ।
- 5,936 एकल-शिक्षकीय स्कूलों में से 4,729 स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त।
- अब केवल 1,207 प्राथमिक शालाएं एकल-शिक्षकीय रह गई है।
- शेष 1,207 शालाओं में भी पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से शिक्षक नियुक्ति की योजना।
- प्राथमिक शालाओं में अनुपात 20 (राष्ट्रीय औसत 29)।

नवा रायपुर में विकास

- नवा रायपुर को आईटी, फार्मा और एजुकेशन हब बनाने पर तेजी से काम हो रहा है।
- आईटी पार्क, डाटा सेंटर, फार्मा हब (142 एकड़ भूमि आवंटित) और मेडिसिटी (200 एकड़ में) का विकास प्रगति पर है।
- बीपीओ और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं।

औद्योगिक और विनिर्माण प्रोत्साहन

- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना।
- रेडीमेड गारमेंट पार्क (30 एकड़, 30 करोड़ रुपए) और फर्नीचर क्लस्टर (40 करोड़ रुपए) का निर्माण।
- लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय।
- परिवहन और लॉजिस्टिक्स
- कार्गो सुविधा उपलब्ध है।
- नवा रायपुर-संबलपुर बैराज जलमार्ग और मेट्रो परियोजना का सर्वे कार्य जारी है।

माओवादी आतंक पर करारा प्रहार

- पिछले 23 महीनों में 487 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2336 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1853 गिरफ्तार किए गए हैं।
- नक्सल प्रभावित इलाकों में अब तक 59 सुरक्षा कैम्प स्थापित।
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास नीति लागू, तीन वर्षों तक प्रतिमाह ₹10,000 स्टाइपेंड, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- बस्तर फाइटर्स बल में 3,202 पदों का सृजन कर स्थानीय युवाओं की सुरक्षा बलों में भर्ती।
- एनआईए और एसआईए के माध्यम से माओवादी नेटवर्क की फंडिंग और सप्लाई चेन पर निर्णायक प्रहार।

छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं का विस्तार

- छत्तीसगढ़ में 41 हजार करोड़ रुपए की लागत से रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय बजट में 6925 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- दोहरीकरणः बस्तर में कोत्तावलसा से किरंदुल (के. के.) 446 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण का काम तेज़ी से जारी है।
- नई रेल लाइनें (मंजूरी): डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा (295 कि.मी.) लंबी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी।
- सर्वेक्षण/डीपीआर हेतु स्वीकृति
- कोरबा-अंबिकापुर (180 कि.मी.) नई लाइन के लिए ₹16.75 करोड़ स्वीकृत।
- गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली (490 कि.मी.) लाइन के सर्वेक्षण के लिए ₹12.25 करोड़ मंजूर।
- डबल लाइनः सरडेगा-भालुमुडा (37 कि.मी.) डबल लाइन परियोजना के लिए ₹1360 करोड़ का प्रावधान।
- वंदे भारत एक्सप्रेसः रायपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-नागपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है।

नारी शक्ति का सम्मान

- छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट) निर्माण का कार्य पुनः सौंपा।
- रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कोतरलिया में 15 अगस्त 2025 से रेडी-टू-ईट निर्माण यूनिट का हुआ शुभारंभ।
- प्रथम चरण में रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा और सूरजपुर जिले में रेडी टू ईट-पूरक पोषण आहार निर्माण/वितरण का शीघ्र होगा क्रियान्वयन।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

- छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा किया।
- वर्ष 2025 में 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 13.58 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित।
- संग्राहकों को 746.87 करोड़ पारिश्रमिक भुगतान।
- इस योजना से लाभान्वित हो रहे 12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक।

वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टाधारक की मृत्यु के बाद वारिसों के नामांतरण की सुविधा।
- नामांतरण से पीएम किसान सम्मान निधि, धान खरीदी आदि योजनाओं का लाभ
- छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे- 4,83,222 (देश में सर्वाधिक)।
- सामुदायिक वन अधिकार- 48,251 पट्टे वितरित।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार- 4,396 पट्टे वितरित।

जीएसटी में सुधार

- मुख्य टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत
- शराब / तंबाकू पर 40 प्रतिशत टैक्स
- रोजमर्रा की वस्तुओं पर राहत ब्रेड, रोटी आदि पर जीएसटी मुक्त
- कपड़े / फुटवियर (2.500 रूपए तक) 5 प्रतिशत
- स्वास्थ्य / जीवन बीमा प्रीमियम 5 लाख रूपए तक छूट
- जीएसटी 2.0 से आम जनता को टैक्स राहत, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा
- अनारक्षित वर्ग को एक बार अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट।
- आरक्षित वर्ग को पूर्व निर्धारित छूट के अलावा अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट।

विद्युत सुविधा विकास और विस्तार

- राज्य स्थापना (सन् 2000) के समय बिजली घरों की कुल क्षमता 1,400 मेगावाट।
- वर्तमान उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट, (स्टेट, निजी और केंद्रीय सेक्टर की भागीदारी से)
- 32,000+ मेगावाट क्षमता वाले बिजलीघर स्थापित करने के लिए एमओयू (ताप, पंप स्टोरेज, परमाणु, बैटरी स्टोरेज, सौर ऊर्जा)।
- भविष्य लक्ष्य 60,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन।
- प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2,211 यूनिट (राष्ट्रीय औसत 1,255 यूनिट)।
- ग्रामीण विद्युतीकरण सभी 19,609 गाँवों में बिजली पहुँची
- 13,000+ मजरा-टोला हुए विद्युतीकृत
- पीएम जनमन, धरती आबा, नियद नेल्ला नार योजना से 80,000 घर रौशन
- सौर ऊर्जा पीएम कुसुम वर्ष 2025 में इस योजना के तहत 4100 करोड़ के निवेश से 675 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य और 20 हजार सोलर पम्प लगाने की योजना, वर्तमान में 7 मेगावाट सौर विद्युत का उत्पादन
- मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA)
- घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट/माह तक बिजली बिल में 50% तक की छूट।
- निःशुल्क बिजलीः एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति

- सब्सिडीः केंद्र और राज्य सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए बड़ी सब्सिडी दे रही है: 1 kW: ₹45,000/2 kW: ₹90,000/3 kW: ₹1,08,000
- प्रगतिः अब तक 55 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं, जिनमें से 5 हजार घरों में सिस्टम लग चुका है और 16 हजार पर काम जारी है।
- लक्ष्यः मार्च 2027 तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है।
- सरकारी परिसरः 2,600 से अधिक सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं।
- सोलर पार्कः आगामी दो वर्षों में 2000 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित होंगे।
- अन्य योजनाएं: 53 गाँव 'सोलर विलेज' के लिए चुने गए हैं, दुर्गम क्षेत्रों में 330 मेगावॉट के मिनी ग्रिड प्लांट और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है।
- बैटरी स्टोरेजः राजनांदगांव में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा है, जिससे 5 लाख यूनिट बिजली उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी।

बिजली का 'शॉक' लगने की तैयारी

छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी ने दिखाया 6300 करोड़ का 'पुराना घाटा', फिर बढ़ सकते हैं दाम

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया है। इस याचिका की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चालू कामकाज में मुनाफा होने के बावजूद, कंपनी ने 'पुराने घाटे' का हवाला देकर भारी-भरकम राजस्व की मांग की है।

मुनाफे के बावजूद 'घाटे' का गणित

पॉवर कंपनी की याचिका में दो अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं जो विरोधाभासी लगते हैं:

नया सत्र (2026-27): कंपनी को प्रचलित दरों से 756 करोड़ रुपये का फायदा होने का अनुमान है।

पुराना बोझ: पिछले वर्षों का अंतर (Revenue Gap) करीब 7,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

नेट डिमांड: नए मुनाफे को पुराने घाटे में घटाने के बाद भी कंपनी ने 6,300 करोड़ रुपये की राजस्व कमी बताई है, जिसे पूरा करने के लिए बिजली महंगी करना ही एकमात्र विकल्प बचता है।

क्या वाकई 20% तक महंगी होगी बिजली?

कंपनी की गणना के अनुसार उसे कुल 32,500 करोड़ रुपये के राजस्व की जरूरत है। पिछले अनुभवों को देखें तोपिछली बार कंपनी ने 5,000 करोड़ का घाटा बताया था, जिसे आयोग ने काट-छाँट कर केवल 500 करोड़ माना था। इसके कारण बिजली की दरें 20% बढ़ने के बजाय मात्र 2% के आसपास बढ़ी थीं।

इस बार यदि आयोग ने कंपनी के 6,300 करोड़ के दावे को बड़े हिस्से में स्वीकार कर लिया, तो बिजली दरों में भारी उछाल आ सकता है।

पॉवर कंपनी का 'बजट' और राजस्व मांग

- अनुमानित कुल खर्च: ₹ 25,460 करोड़ (2026-27 के लिए)
- अनुमानित वर्तमान आय: ₹ 26,216 करोड़
- संचालन लाभ: ₹ 756 करोड़ (प्लस में)
- पुराना संचित घाटा: ₹ 7,000 करोड़ से ज्यादा
- शुद्ध राजस्व कमी (Deficit): ₹ 6,300 करोड़ (जिसे वसूलने के लिए टैरिफ बढ़ेगा)

अब आयोग की 'कैंची' पर टिकी उम्मीदें

नियामक आयोग अब इस याचिका की गहन समीक्षा करेगा। आयोग यह देखेगा कि:

- क्या कंपनी द्वारा बताया गया 6,300 करोड़ का पुराना घाटा वास्तविक है?
- क्या कंपनी ने बिजली खपत का सही अनुमान लगाया है?
- जनसुनवाई के दौरान आम जनता और औद्योगिक घरानों की आपत्तियों के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।

आम उपभोक्ता पर सीधा असर

यदि आयोग घाटे की राशि को ज्यादा मानता है, तो इसका सीधा असर घरेलू और औद्योगिक बिजली बिलों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़, जो एक बिजली सरप्लस राज्य है, वहां पुराने घाटों की वसूली आम उपभोक्ताओं से करना हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।

मौत के सौदागरों को 'वॉकओवर'

रायपुर में पकड़ी गई नकली दवाओं की जांच फाइल हुई ठंडी, आखिर क्यों इंदौर जाने से कतरा रहा विभाग?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा करने वाला खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) अब खुद सवालों के घेरे में है। 17 दिन पहले रायपुर के एक ट्रांसपोर्ट से बरामद पौने दो लाख की नकली एंटीबायोटिक दवाओं का 'मालिक' कौन है? इसका जवाब विभाग के पास नहीं है। विभागीय सुस्ती का आलम यह है कि जिस इंदौर लिंक से मुख्य आरोपी का सुराग मिलना था, वहां जाने के लिए टीम पिछले 10 दिनों से केवल 'फाइलें' पलट रही है।

1. संगठित गिरोह का 'घोस्ट एड्रेस'

नकली दवाओं के रैपर पर छपे पतों ने इस पूरे सिंडिकेट की भयावहता उजागर कर दी है:

चेन्नई कनेक्शन: रैपर पर जिस कंपनी का नाम है, वह सालों पहले बंद हो चुकी है।

हिमाचल का फर्जीवाड़ा: जिन वे कंपनियों का जिक्र है, धरातल पर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं मिला। स्पष्ट है कि यह कोई छोटी-मोटी हेराफेरी नहीं, बल्कि हिमाचल से लेकर चेन्नई तक फैला एक संगठित ड्रग माफिया है, जो छत्तीसगढ़ के मरीजों को 'ज़हर' परोस रहा है।

2. संदिग्धों को 'सेफ पैसेज' देने की कोशिश?

दवाएं मिलने के बाद विभाग ने सारंगढ़ और भाटापारा के कुछ रसूखदार कारोबारियों पर छापा मारा था। दावा था कि यही लोग इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन 17 दिन बाद भी उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न जुटा पाना विभाग की कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करता है। चर्चा है कि क्या जांच में देरी कर इन 'बड़े चेहरों' को सुराग मिटाने का वक्त दिया जा रहा है?

3. 'मुहूर्त' के इंतजार में कहीं मिट न जाएं सबूत

दवाओं के अवैध कारोबार में रिकॉर्ड बहुत जल्दी नष्ट किए जाते हैं। 17 दिन की देरी का मतलब है कि इंदौर का वह सप्लायर अब तक अपना ठिकाना बदल चुका होगा। विभाग का यह तर्क कि "तीन-चार दिन में टीम जाएगी", अपराधियों के लिए किसी 'चेतावनी' से कम नहीं है कि वे अपनी फाइलें और स्टॉक ठिकाने लगा लें। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर में लावारिस माल का मिलना और फिर विभाग का सुस्त पड़ जाना यह बताता है कि प्रदेश में ड्रग कंट्रोलिंग सिस्टम कितना लचर है।

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव : कलेक्टरेट में होगी नामांकन प्रक्रिया

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार प्रेस क्लब रायपुर के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष (01), उपाध्यक्ष (01), महासचिव (01), संयुक्त सचिव (02) एवं कोषाध्यक्ष (01) पद शामिल हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति एवं जमा करने की प्रक्रिया 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्टरेट परिसर रायपुर के कक्ष क्रमांक क-09 में होगी। नाम निर्देशन पत्रों की जांच (संवीक्षा) तथा वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन 9 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे कक्ष क-09, कलेक्टरेट परिसर में किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 10 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदान 13 जनवरी 2026 को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रेस क्लब रायपुर में होगा। मतदान समाप्त होते ही उसी दिन मतगणना भी प्रेस क्लब परिसर में की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र कलेक्टरेट परिसर रायपुर के कक्ष क्रमांक क-09 से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतदाता सूची का शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन शुल्क 5000 रुपये तथा अन्य पदों के लिए 2000 रुपये रखा गया है।

पिछले साल घटा अपराध, गंभीर अपराधों और नशे के नेटवर्क पर वार

रायपुर। रायपुर पुलिस ने वर्ष 2025 के अपराध से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि शहर में कुल आपराधिक मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि सख्त कार्रवाई और लगातार अभियान का असर गंभीर अपराधों और नशे के नेटवर्क पर साफ दिखाई दे रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्ष 2025 के दौरान दर्ज अपराधों की संख्या में 2024 की तुलना में गिरावट आई है। रायपुर पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच जिले के सभी थानों में कुल 15 हजार 885 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 17 हजार 703 थी। हत्या के मामलों की बात करें तो वर्ष 2025 में कुल 90 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 85 मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 167 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती के मामलों में भी कमी दर्ज की गई। पूरे वर्ष में केवल 7 डकैती के मामले सामने आए, जिनमें से 6 मामलों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

लूट के मामलों में मामूली गिरावट देखी गई है। वर्ष 2025 में लूट के 71 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 73 थी। इस तरह लूट की घटनाओं में करीब 2.74 प्रतिशत की कमी आई है। चोरी के मामलों में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2024 में चोरी के 1497 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1442 रह गई। वहीं धोखाधड़ी के मामलों में इस साल 292 प्रकरण सामने आए।

नशे के कारोबार के खिलाफ रायपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में बड़ा अभियान चलाया। नारकोटिक एक्ट के तहत 271 मामलों में कार्रवाई करते हुए 445 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ, वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा नाइजीरिया के दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2025 में गुंडा और निगरानी बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जिला दंडाधिकारी के समक्ष कुल 33 प्रतिवेदन पेश किए गए, जिनमें से 5 गुंडा और निगरानी बदमाशों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी किए गए।

साप्ताहिक शहर सत्ता

छत्तीसगढ़ PDS का 'शुद्धिकरण' या गरीबों पर प्रहार?

एक तरफ 10 हजार 'अमीर' बेनकाब, दूसरी तरफ 12 लाख गरीबों का राशन दांव पर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में इस वक्त उथल-पुथल मची है। राज्य सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' और ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए राशन कार्डों के शुद्धिकरण का अभियान छेड़ा है। इस अभियान के दो पहलू सामने आए हैं: एक ओर रायपुर के 10,361 'करोड़पति' फर्जी कार्डधारी पकड़े गए हैं, तो दूसरी ओर केवाईसी की तकनीकी पेचीदगियों के कारण 12 लाख गरीब परिवारों की थाली से चावल गायब हो गया है।

फर्जीवाड़े का भंडाफोड़: 6 लाख की आय, फिर भी 'गरीब' कार्ड

राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग ने उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो इनकम टैक्स और GST भरने के बावजूद बीपीएल (BPL) और अंत्योदय कार्ड का लाभ ले रहे थे।

रायपुर का हाल: अकेले रायपुर जिले में 10,361 फर्जी कार्ड निरस्त किए गए हैं। इनमें 6 लाख से अधिक सालाना आय वाले और कार-एसी रखने वाले परिवार भी शामिल थे।

बड़ी रिकवरी: विभाग अब इन अमीरों से पिछले 3 साल के राशन की बाजार भाव (Market Rate) पर वसूली करेगा। पैसा न देने पर FIR तक की तैयारी है।

निष्क्रिय आधार का खेल: राज्य भर में 1.55 लाख ऐसे कार्ड मिले हैं जो निष्क्रिय (Inactive) आधार नंबरों पर चल रहे थे।

डिजिटल 'सिस्टम' की मार: 12 लाख गरीबों का रुका दाना-पानी

जहाँ अमीरों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं विभाग की एक 'गलत सेटिंग' ने गरीबों को संकट में डाल दिया है। विभाग ने नियम बना दिया है कि यदि परिवार के एक भी सदस्य की ई-केवाईसी अधूरी है, तो पूरे परिवार का राशन

रोक दिया जाएगा।

सामूहिक सजा: 4 या उससे अधिक सदस्य वाले परिवारों का आवंटन पूरी तरह बंद है, जबकि नियमतः केवल उस व्यक्ति का राशन कटना चाहिए जिसकी केवाईसी नहीं हुई है।

बीमारों पर संकट: सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि 1,000 से अधिक कुष्ठ रोगी और हजारों बुजुर्ग, जो बायोमेट्रिक देने में सक्षम नहीं हैं, पिछले 3 महीनों से दाने-दाने को मोहताज हैं।

पात्रता के कड़े नियम: अब ये नहीं बन पाएंगे 'गरीब'

विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी के लोग अब राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे:

- जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक है।
- जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 7.5 एकड़ असिंचित जमीन है।
- जो GST पंजीकृत व्यवसायी हैं।
- जिनके पास चार पहिया वाहन, एसी या फ्रिज जैसी सुख-सुविधाएं हैं।

विपक्ष के आरोप और घोटाले की आशंका

एक ओर जहाँ ई-केवाईसी को सुशासन बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केवाईसी के बहाने गरीबों का राशन रोकना एक सोची-समझी साजिश है। आरोप है कि भौतिक सत्यापन न कराकर गरीबों के हक का चावल बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।

अमीरों पर कार्रवाई, गरीबों की समस्या

- **कुल कार्रवाई :** 1 लाख से ज्यादा फर्जी कार्ड रद्द किए गए।,12 लाख पात्र लोगों का राशन रुक गया।
- **आय सीमा :** 6 लाख से ऊपर आय वालों के कार्ड निरस्त।,1 सदस्य की केवाईसी न होने पर 100% कटौती।
- **वसूली/नुकसान :** बाजार भाव पर राशन की वसूली होगी।,कुष्ठ रोगियों को 3 महीने से अनाज नहीं मिला।
- **तकनीकी पहलू :** आधार-पैन लिंक होने से पारदर्शिता आई।,ऐप और सर्वर की दिक्कतों से गरीब परेशान।
- **मुख्य लक्ष्य :** फर्जीवाड़ा रोककर सरकारी धन बचाना।,नियम की सख्ती से गरीबों की थाली प्रभावित।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का डिजिटल 'फिल्ट्रेशन' जरूरी है ताकि अमीरों द्वारा गरीबों का हक मारना बंद हो। लेकिन, एक सदस्य की तकनीकी खामी के कारण पूरे कुनबे को भूखा रखना 'सुशासन' नहीं बल्कि 'प्रशासनिक संवेदनहीनता' की श्रेणी में आता है।

एएसपी गिरपुंजे के हत्यारे ढेर

सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए

रायपुर। सुकमा जिले में हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में डीवीसीएम मंगतू व कोण्टा एरिया कमेटी का एसीएम हितेश भी शामिल है, जो सुकमा के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल थे। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शव के अलावा अत्याधुनिक हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया है।

एसीएम व पीपीसीएम ढेर

सुकमा में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त एसीएम डुंगा मड़कम उर्फ पंचुगा निवासी पूवर्ती व पीपीसीएम आयती मुचाकी उर्फ जोगी निवासी पामेड़ के रूप में हुई है। एसपी बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि अभियान के दौरान डीआरजी बीजापुर की टीम का माओवादियों के साथ सुबह पांच बजे से ही रुक रुककर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ समाप्ति के बाद दोनों के शव के साथ ही एसएलआर रायफल व 12 बोर देशी कट्टा के साथ विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का ईनाम घोषित था।

डीवीसीएम मंगडू व एसीएम हितेश भी ढेर

बीजापुर जिले में तड़के हुई मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने डीवीसीएम मंगडू व एसीएम हितेश समेत 12 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुकमा और बीजापुर में मारे गए नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। सुकमा में मारे गए 12 नक्सलियों में डीवीसीएम मेंबर मंगडू व एसीएम हितेश का भी शव मिला है.

सीएम साय ने कहा-बस्तर में स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा है. जहां अब हिंसा नहीं, शांति ही एकमात्र विकल्प बन चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है।

हिड़मा के उत्तराधिकारी बारसे देवा ने 19 साथियों के साथ किया समर्पण

जगदलपुर। समर्पण के दौरान नक्सलियों ने 48 अत्याधुनिक हथियार भी सौंपे, इन हथियारों में अमेरिकी कोल्ट राइफल व इजरायल निर्मित टैवोर राइफल भी शामिल है। नक्सली अपने साथ 20 लाख से अधिक नगद रकम भी साथ लेकर पहुंचे थे। वर्ष 2026 की शुरूआत में माओवादी संगठन को लगा यह बड़ा झटका है। कुख्यात नक्सली नेता और मारे गए नक्सली लीडर सीसी मेंबर माड़वी हिड़मा का उत्तराधिकारी माने जाने वाले बटालियन चीफ बारसे देवा ने शनिवार को तेलंगाना के

डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष अपने 19 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। सपर्मण कर दिया है। सीसी मेबर हिड़मा के मारे जाने के बाद देवा को माओवादी संगठन ने बटालियन चीफ नियुक्त किया था। माओवादियों की सबसे घातक मानी जाने वाली पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरीला आर्मी) बटालियन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है। देवा संगठन के लिए अत्याधुनिक हथियार जुटाने और हथियारों की सप्लाई चेन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता रहा है।

कांगेर घाटी में मिली अनोखी 'ग्रीन गुफा'

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश में विख्यात है। इसी कड़ी में अब कांगेर घाटी में एक और अनोखी प्राकृतिक स्थलाकृति सामने आई है, जिसे "ग्रीन केव" (ग्रीन गुफा) नाम दिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और वन्य धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वन मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन गुफा के पर्यटन मानचित्र में शामिल होने से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति प्राप्त होगी और शीघ्र ही पर्यटक इस अद्भुत गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। वन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण किए जाने के बाद शीघ्र ही इस गुफा को पर्यटकों के लिए खोले जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि यह ग्रीन गुफा कोटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों और छत से लटकती चूने की आकृतियों (स्टैलेक्टाइट्स) पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे "ग्रीन केव" नाम दिया गया है। चूना पत्थर और शैल से निर्मित यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ और विशिष्ट गुफाओं में से एक मानी जा रही है। ग्रीन गुफा तक पहुंचने का मार्ग बड़े-बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है। गुफा में प्रवेश करते ही सूक्ष्मजीवी जमाव से ढकी हरी दीवारें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जहां से भीतर की ओर चमकदार और विशाल स्टैलेक्टाइट्स तथा फ्लो-स्टोन (बहते पानी से बनी पत्थर की परतें) देखने को मिलती हैं, जो गुफा की प्राकृतिक भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

चलते चलते...

हम आशा ही कर सकते हैं कि 2026 में हालात 2025 की तुलना में बेहतर होंगे। नए साल की शुरुआत बीते साल पर आत्ममंथन का अवसर देती है। 2026 इसी के लिए एक आमंत्रण है। आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का भी। हम आशा ही कर सकते हैं कि 2026 में हालात बेहतर होंगे। नए साल की शुरुआत बीते साल पर आत्ममंथन का अवसर भी देती है। विशेष रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना को उनके शासन के प्रति बढ़ती अलोकप्रियता के बारे में समय रहते सचेत न कर पाना हमारी कूटनीतिक विफलता रही। लगता है कि हमने वहां के विपक्ष के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे बिना अपने सारे दांव उन्हीं पर लगा दिए। जमात-ए-इस्लामी जैसे अतिवादी दलों और भारत-विरोधी तत्वों को वित्तपोषित और प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की भूमिका का आकलन न कर पाना भी एक चूक रही।

सत्ता में बैठे लोग केवल वहीं पर सक्रिय होते हैं, जहां वोट दांव पर हों। नागरिकों की ओर से यदि कोई संगठित पहल नहीं हो तो सरकारें बस इंतजार करती रहती हैं कि सालाना संकट अपने आप टल जाए। लेकिन 2025 ने संकेत दिया है कि लोग अब कह रहे हैं : बहुत हुआ। 2026 वह वर्ष हो सकता है, जब नागरिक जवाबदेही की मांग करें। और तब सरकार को कार्रवाई करनी ही होगी।

2025 में जारी वायु संकट- जिसने उत्तर भारत को हांफने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली के निवासियों का दम घोंट दिया- ने भी नागरिकों को यह पूछने पर विवश किया कि यह समस्या हर साल क्यों दोहराई जाती है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इसके भयावह नतीजे अच्छी तरह से मालूम हैं, तब भी सरकार इसे ठीक करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाती?

बिहार में एसआईआर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, और अब जिस तरीके से इसे पूरे देश में किया जा रहा है, वह बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देता है। यहां मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल नहीं हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, वह जरूर चिंताओं के दायरे में है। मेरे विचार से, 2025 को चार केंद्रीय मुद्दों के लिए याद किया जाएगा; चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर उठते सवाल; दिल्ली तथा उससे सटे क्षेत्रों में साफ हवा का संकट; हमारे पड़ोस में जारी उथल-पुथल और ट्रम्प की अप्रत्याशित हरकतों के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में पैदा हुई अस्थिरता।

कोंदा-भैरा के गोठ

-रायगढ़ जिला म बीते 27 दिसंबर के खनन विरोधी प्रदर्शन के बेरा एक महिला आरक्षक संग होय अभद्रता ह पूरा छत्तीसगढ़ के शांत अउ सुसंस्कृत लोगन ल दंदोरत हे जी भैरा.

-हव जी कोंदा.. सोशलमीडिया म किंजरत विडीयो ल महूँ देखे हौं.. मोला लागथे के छत्तीसगढ़ के इतिहास म पहिली बेर अइसन घटना घटे हे जेमा महिला आरक्षक संग प्रदर्शन करइया मन मानवता के सीमा नाहके हें.

-हव भई.. विडीयो म सफा दिखत हे वो नोनी ह चिरहा कपड़ा म लपटाए खेत म अकेल्ला डरभुतहा बानी के जनावत हे अउ एक झन प्रदर्शनकारी ह वोकर हाथ अउ देंह म बाँचे कपड़ा ल झींकत हे अउ दूसर ह विडीयो बनावत हे.

-कतकों बेर अइसन देखे ले मिले हे संगी के अइसन कोनो किसम के धरना प्रदर्शन होथे तेमा कतकों असमाजिक किसम के लोगन कलेचुप खुसर जाथे अउ गड़बड़ी करथे.

-हव जी अइसन महूँ देखे हौं.. हमन खुद एक पइत भाखा संस्कृति ल लेके प्रदर्शन करे रेहेन तेमा एमा एक राजनीतिक मनखे ह अमाके शांत माहौल ल बिगाड़े के उदिम करे रिहिसे.

2026 में खुद से थोड़ा और बेहतर कैसे बनें?

एन रघुरामन

"कृपया 1 से 4 जनवरी तक सुबह की सैर से बचें। इस समयावधि में फिट रहने का रिजॉल्यूशन लेने वाले लोगों की बड़ी और अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने की संभावना है। बहरहाल, 5 जनवरी से हालात सामान्य हो सकते हैं।'

इस साल मुझे मिला यह चेतावनी-संदेश पहले तो मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आया, लेकिन फिर इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि अधिकांश रिजॉल्यूशन असफल क्यों हो जाते हैं? और यह नाकामी मानव व्यवहार के बारे में क्या बताती है?

इसी के चलते मैं एक 'उत्तम' न्यू ईयर रिजॉल्यूशन के लिए उपाय तलाशने लगा। हर जनवरी हममें से लाखों लोग बिना किसी डेटा के साहसी अनुमान लगाते हैं, बिना किसी फीडबैक के रणनीतियां अपनाते हैं और जिम की सदस्यताएं ले लेते हैं।

जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, वह 'हम' जिसने रिजॉल्यूशन लिया था, और वह 'हम' जिसे उसे निभाना था- दोनों आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे से तलाक की अर्जी लगा देते हैं! ठंडा मौसम हमारे भीतर की आग को बुझा देता है और हममें से अधिकांश लोग पिछले साल के दिसंबर वाले संस्करण में लौट आते हैं। क्यों?

क्योंकि जब हम यह अनुबंध करते हैं, तो हम भविष्य की अपनी इच्छा-शक्ति का अनुमान लगा रहे होते हैं। हम अपने एक आदर्श रूप की कल्पना करते हैं- अनुशासित, सही भोजन करने वाला, सदाचारी, भोर में उठने वाला- न कि अनुभवों से जाने गए हमारे उस वास्तविक रूप की, जो अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबा देता है।

मानव-व्यवहार का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान में इसे 'प्रजेंट बायस' कहा जाता है, जो 1 जनवरी को सबसे अधिक दिखाई देता है। कॉलेज के दिनों में, नववर्ष के बाद आने वाले पहले रविवार को 'डिच न्यू ईयर्स रिजॉल्यूशन डे' कहा जाता था। और चूंकि आज रविवार है, इसलिए एक बड़ा वर्ग अपने रिजॉल्यूशंस को ताक पर रखने में व्यस्त होगा।

इससे यह सवाल उठ खड़ा होता है कि यदि खराब पूर्वानुमान, समय के प्रति अनियमितता और हमारे इरादों और व्यवहार के बीच मौजूद खाई 'तलाक' की उपरोक्त वर्णित अर्जियों के लिए जिम्मेदार हैं, तो फिर इस रिश्ते को चलाए रखने के लिए क्या कारगर है?

मानव-व्यवहार का अध्ययन करने वाले कहते हैं कि 'एप्रोच-ओरिएंटेड' लक्ष्य, 'अवॉइडेंस' वाले लक्ष्यों की तुलना में 26% अधिक सफलता देते हैं। जैसे 'सप्ताह में तीन-चार बार व्यायाम करना' जैसे वाक्यों वाला रिजॉल्यूशन '1 जनवरी से जंक फूड खाना बंद करना' की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है।

इसी तरह, 'हर रात 20 मिनट किताब पढ़ना', 'स्क्रीन टाइम 20 मिनट कम करना' से अधिक प्रभावी है। 'अवॉइडेंस' लक्ष्य निरंतर सतर्कता और इच्छा-शक्ति की मांग करते हैं, जबकि 'एप्रोच' लक्ष्य एक लय बनाते हैं। सफलता में चॉइस-आर्किटेक्चर की बड़ी भूमिका होती है।

इसका अर्थ है जिस परिवेश या संदर्भ में लोग निर्णय लेते हैं, उन्हें इस तरह से गढ़ते हुए विकल्पों को प्रस्तुत करना कि इससे उनके चयन प्रभावित हों। और वह भी उनकी स्वतंत्रता को सीमित किए बिना।

थेलर और सनस्टीन द्वारा गढ़ी गई यह अवधारणा मानती है कि हर निर्णय-परिवेश की अपनी एक संरचना होती है, चाहे वह जानबूझकर बनाई गई हो या नहीं, और वह नतीजों को प्रभावित करती है- कैंटीन में भोजन की व्यवस्था से लेकर घर में किताबें रखने तक।

आज अनेक घरों के हर कमरे में टीवी स्क्रीन हैं, किताबों की अलमारियां नहीं; इसलिए बच्चों को पढ़ने की ओर आकर्षित करना कठिन हो जाता है। जिन घरों में किताबें होती हैं और जहां पैरेंट्स पढ़ते हैं, वहां बच्चे भी उस आदत को अपना लेते हैं। इसीलिए लक्ष्य छोटा रखें, जैसे रोज सुबह उठते ही तीन पुश-अप करना।

इस संकल्प के कई दिनों तक टिके रहने की अधिक संभावना है और धीरे-धीरे यह आदत बन जाता है, जिसके बाद उसे बढ़ाया जा सकता है- जैसा कि डॉ. बी.जे. फॉग की किताब 'टाइनी हैबिट्स मैथड' में बताया गया है। तो यदि आप 2026 में अपने आज के रूप से थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, तो तीव्रता को प्राथमिकता देने से पहले छोटे लक्ष्यों के साथ निरंतरता का अभ्यास करें।

फंडा यह है कि जब आप सेल्फ-इम्प्रूवमेंट को किसी निवेश की तरह देखेंगे, जिसमें आपके फैसले ठोस साक्ष्यों और उत्प्रेरकों से तय होते हैं और जो आपकी सूझ-बूझ के अनुरूप होते हैं, केवल तभी आप अपने सफल होने की सम्भावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा सकेंगे।

बंगाल का चुनाव ममता की सबसे कठिन परीक्षा

बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सामने पांच चुनौतियां हैं। पहली, 15 साल की सत्ता विरोधी लहर से पार पाना। दूसरी, संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटना। तीसरी, तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों के चलते वोटरों का खोया भरोसा वापस पाना। चौथी, एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग से टकराना। लेकिन पांचवीं चुनौती उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यह है मुस्लिम वोटरों का तृणमूल से छिटककर ओवैसी की एआईएमआईएम और टीएमसी के बागी नेताओं के पाले में जाना।

तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि वे मुस्लिम वोटबैंक को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में ममता ने जन-भावनाओं को लामबंद करने के लिए मनरेगा का नाम बदलने संबंधी कानून को औजार बनाया है। एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि 'मुझे शर्म महसूस हो रही है। एक विधेयक लाया गया है। गांधीजी के नाम पर बनी मनरेगा में अब उन्हीं का नाम नहीं होगा। हम राष्ट्रपिता को भूल रहे हैं। मैं इस देश की हूं तो इसके लिए मैं अपने सिवाय किसी को दोष भी नहीं दे सकती। हमने 'कर्मश्री' योजना शुरू की थी, इसका नामकरण अब गांधीजी के नाम पर किया जाएगा।' लेकिन मनरेगा का नाम बदलने की बहस जल्द ही साम्प्रदायिक रंग में रंग गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने कहा- 'यह विधेयक महात्मा गांधी के सम्मान के लिए ही लाया गया है, क्योंकि वे मानते थे कि राम ही भारत है और भारत ही राम हैं। तृणमूल तो 'जयश्री राम' के नारे को भी अनुचित मानती है। कुछ लोग राम के बजाय बाबर के रास्ते पर चलना चाहते हैं।' लेकिन इस सियासी तू-तू-मैं-मैं ने 'वीबी-जी राम जी' कानून के असल असर को दबा दिया। इस कानून का बड़ा फायदा है कि भुगतान वाले कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। लेकिन एक कमी भी है कि योजना के खर्च का 40% बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। हालांकि, हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों को 10% ही हिस्सेदारी देनी होगी।। केंद्र का दावा है कि पहले मनरेगा के तहत राज्यों को दिए गए पैसे में घोटाले हुए थे। केंद्र-राज्य हिस्सेदारी तय करने से योजना अधिक पारदर्शी बनेगी। हालांकि भाजपा और सहयोगी दलों के शासन वाले कई राज्यों ने ही इस पर नाखुशी जाहिर कर दी है। एनडीए की सहयोगी टीडीपी शासित आंध्र प्रदेश ने साफ कर दिया है कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल होगा।

'लाडकी बहिन योजना' के कारण पहले से वित्तीय दबाव झेल रहा महाराष्ट्र भी इससे खासा प्रभावित होगा। 'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत 2026 में राज्य में अनुमानित 1.51 लाख करोड़ के खर्च में से महाराष्ट्र को करीब 6 हजार करोड़ अतिरिक्त देने होंगे। तो वापस आते हैं कि क्या मनरेगा विवाद ममता बनर्जी को खोई चुनावी साख वापस दिला सकता है? शायद नहीं। लेकिन यह प्रचार के दौरान ममता सरकार पर लगे घोटालों के दागों से ध्यान भटकाने में मददगार जरूर बन सकता है। ममता जल्द ही 71 साल की हो जाएंगी। उनके उत्तराधिकारी और भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में उतने लोकप्रिय नहीं हैं। वे रूखे मिजाज वाले हैं और अपमानजनक व्यवहार भी कर सकते हैं। 2024 में ममता बनर्जी ने कुछ वक्त के लिए उनसे दूरी भी बना ली थी, लेकिन कई घोटाले सामने आने पर उनकी वापसी कराई गई है। इधर, पड़ोसी बांग्लादेश की उथल-पुथल इस चुनाव में दोधारी तलवार जैसी हो सकती है। एसआईआर के चलते तृणमूल के वोटर समझे जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या घटी है। लेकिन ढाका में बढ़ता साम्प्रदायिक तनाव पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटरों को ममता के पक्ष में लामबंद कर सकता है। क्योंकि वे जानते हैं कि ओवैसी और हुमायूं कबीर टीएमसी वोटरों का छोटा-सा हिस्सा ही तोड़ सकते हैं। ऐसे में ममता ही भाजपा से उनका बचाव कर सकती हैं। लेकिन यदि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने में नाकाम रहती है तो बंगाल चुनाव पर इसका गम्भीर असर हो सकता है। इससे अब तक पसोपेश में फंसे हिंदू वोटर भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

साप्ताहिक शहर सत्ता

चंद घंटो में पलट गया मादुरो का शासन

150 प्लेन और मात्र 30 मिनट! अमेरिका ने कैद किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शुक्रवार (2 जनवरी 2026) की सुबह सोशल मीडिया पर अपनी सेहत और अन्य मुद्दों पर पोस्ट कर रहे थे, उसी समय वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य घटनाक्रम को अंजाम दिया गया. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ चलाया गया यह बड़े स्तर का सैन्य अभियान कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया गया. इस ऑपरेशन को एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था, जिसकी तैयारी कई महीनों से की जा रही थी.अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन की योजना, अभ्यास और रिहर्सल लंबे समय से चल रही थी. एक बार शुरू होने के बाद यह पूरा अभियान 30 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया और कुछ ही घंटों में मादुरो का शासन खत्म हो गया. हमले से पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास अपनी मौजूदगी चुपचाप बढ़ा दी थी. खुफिया एजेंसियां मादुरो की रोजमर्रा की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थीं. AP की रिपोर्ट के मुताबिक यह तक रिकॉर्ड किया गया कि वे किस समय कहां रहते हैं, उनकी आदतें क्या हैं और यहां तक कि उनके कपड़े और पालतू जानवरों की जानकारी भी जुटाई गई थी.

मादुरो के घर की हूबहू नकल बनाई गई

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ऑपरेशन की तैयारी के लिए मादुरो के आवास की बिल्कुल वैसी ही एक नकली इमारत तैयार की गई थी, जिसमें हर तरह की सुरक्षा और स्टील संरचना शामिल थी. इस मॉडल पर बार-बार अभ्यास किया गया ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे. ट्रंप के अनुसार ऑपरेशन के दौरान करकास शहर की अधिकांश बिजली भी बंद कर दी गई थी, ताकि कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके. यह अभियान उस समय शुरू किया गया जब ट्रंप ने रात करीब 10:46 बजे मिशन को अंतिम मंजूरी दी. मौसम साफ होने का इंतजार किया गया ताकि हेलीकॉप्टर और विमान सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सकें. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद निचले स्तर पर उड़ते हुए आगे बढ़े, ताकि रडार से बचा जा सके।

मेक्सिको और क्यूबा हो सकता है अगला निशाना

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि क्यूबा ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना हो सकता है. वेनेजुएला और क्यूबा दोनों को लेकर लंबे समय से चिंतित रहे रुबियो ने कहा, 'अगर मैं हवाना में रहता और सरकार में होता तो मैं कम से कम थोड़ा तो चिंतित होता.' ट्रम्प ने यह भी कहा कि मेक्सिको के साथ कुछ न कुछ करना ही होगा और साथ ही यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम एक अच्छी महिला हैं, लेकिन वह देश नहीं चला रही हैं. ट्रम्प ने कहा, 'हम उनके (शाइनबाम) साथ बहुत दोस्ताना संबंध रखते हैं, वह एक अच्छी महिला हैं, लेकिन मेक्सिको को कार्टेल चला रहे हैं. वह मेक्सिको नहीं चला रही हैं.' उन्होंने कहा कि उन्होंने शाइनबाम से कई बार पूछा है कि क्या आप चाहती हैं कि हम कार्टेल को खत्म कर दें? लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया है. लैटिन अमेरिका में यूएस की व्यापक योजनाओं पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व पर अब कोई सवाल नहीं उठेंगे. उन्होंने कहा, 'हम अच्छे पड़ोसियों से घिरे रहना चाहते हैं. हम स्थिरता से घिरे रहना चाहते हैं. हम ऊर्जा से घिरे रहना चाहते हैं. उस देश में हमारे पास अपार ऊर्जा है. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसकी रक्षा करें. हमें इसकी अपने लिए आवश्यकता है.'

भारत की पहली प्रतिक्रिया!

वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वहां की स्थिति तेजी से बदल रही है और उस पर लगातार नजर रखी जा रही है. मौजूदा हालात को देखते हुए भारत किसी भी तरह की जल्दबाजी के बजाय स्थिति को समझते हुए आगे की रणनीति अपनाना चाहता है.भारत का मानना है कि वेनेजुएला में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका असर सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है. इसी वजह से भारत इस पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील और महत्वपूर्ण मानते हुए लगातार निगरानी कर रहा है. भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई उसके लिए बेहद अहम है. भारत ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे आपसी मतभेदों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं. भारत का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से हालात और बिगड़ सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि संयम बरतते हुए शांति बनाए रखी जाए और संवाद के रास्ते से समाधान निकाला जाए. भारत ने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है.

सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग! अब तक 20 की मौत

नई दिल्ली। यमन में चल रहे लंबे संघर्ष ने एक बार फिर हिंसक मोड़ ले लिया है. सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने शुक्रवार (2 जनवरी 2026) को हवाई हमले कर यूएई समर्थित Southern Transitional Council के ठिकानों को निशाना बनाया है. इन हमलों में कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में यमन से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करने की घोषणा की थी.

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हमले हद्रामौत प्रांत के सेइयून और अल-खाशा इलाकों में स्थित सैन्य ठिकानों पर किए गए. हमलों में एक सैन्य अड्डे और हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र में हवाई गतिविधियां ठप हो गईं. कई घंटों तक किसी भी विमान की आवाजाही नहीं हो सकी, जिससे आम नागरिकों में भी डर का माहौल बन गया. Southern Transitional Council से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि मारे गए सभी लोग उनके लड़ाके थे, जो इन सैन्य ठिकानों पर तैनात थे. यह पहली बार है जब हाल के महीनों में सीधे STC के ठिकानों को निशाना बनाया गया है.

इन हवाई हमलों से पहले यूएई ने घोषणा की थी कि उसने यमन से अपनी अंतिम सैन्य टुकड़ी भी वापस बुला ली है. अबू धाबी ने स्पष्ट किया कि वह क्षेत्र में तनाव कम करना चाहता है. हालांकि, इससे पहले मुकल्ला बंदरगाह पर हुए हमले को लेकर विवाद भी सामने आया था, जहां कथित तौर पर हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया।

तेलंगाना में दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसका असर राज्य की ग्रामीण राजनीति पर गहरा होगा. पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री डी. अनसूया सीताक्का (Seethakka) की अगुवाई में राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए 'दो बच्चों' की लागू नीति को खत्म करने वाला विधेयक पारित करा लिया है.

तेलंगाना में अब 2 से अधिक संतान वाले लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा. यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि पहले तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत, मंडल या जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए यह अनिवार्य था कि उसके दो से ज्यादा बच्चे न हों. इस नियम के चलते अब तक हजारों सक्षम और योग्य नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने से वंचित रहना पड़ता था. हालांकि, आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार पहले एक अध्यादेश (Ordinance) लाई थी, जिसे विधानसभा में पूर्ण विधेयक का रूप देकर कानूनी रूप से मंजूरी दी गई है. इस मौके पर पंचायत राज मंत्री सीताक्का ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला जनता की आवाज को बल मिलने जैसा है. उन्होंने कहा, "इस संशोधन के बाद अब दो से ज्यादा बच्चों की परवरिश करने वाले लोग भी पंचायत, मंडल और जिला परिषद के चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से पात्र होंगे." उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मकसद लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के दायरे को व्यापक बनाना है, ताकि कोई भी समाज या वर्ग राजनीतिक प्रक्रिया से अलग न रह जाए. इस फैसले को राज्य की राजनीति में जनप्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है।

उत्तर कोरिया ने दागी संदिग्ध मिसाइल, जापान सागर में तनाव

नई दिल्ली। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप और आसपास के इलाके में तनाव बढ़ा दिया है. दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के पास समुद्र की दिशा में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है. इस घटनाक्रम पर जापान और अमेरिका समेत क्षेत्रीय देश नजर बनाए हुए हैं. दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बयान जारी कर कहा, 'उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर (जापान सागर) की ओर एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है.' फिलहाल मिसाइल की रेंज और प्रकार को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. पान के रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर कोरिया द्वारा संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने की पुष्टि की है. हालांकि, अभी तक किसी तरह के नुकसान या आपात स्थिति की कोई सूचना नहीं दी गई है।

क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें

फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी

नई दिल्ली। आज भी फ्लाइट में कई यात्री अनजाने में या लापरवाही से वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उड़ान के दौरान आग, धुएं या शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं की वजह बन सकती हैं. यह वजह और कोई नहीं, बल्कि हर किसी के सामान में पाया जाने वाला power bank है. क्या आप जानते हैं फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का इस्तेमाल करना या उससे मोबाइल चार्ज करना मना है?देश में बहुत से एयरपोर्ट पर नजर आया है कि यात्री फ्लाइट में पावर बैंक को लेकर आज भी लापरवाही बरत रहे हैं जबकि इसके नियम नवंबर 2025 में ही तय कर दिए गए थे. नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने उस समय साफ-साफ कहा था कि पावर बैंक और लिथियम बैटरी वाले उपकरण विमान के अंदर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.DGCA के नवंबर में जारी सर्कुलर के मुताबिक, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और पावर बैंक में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरियां अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं जो ज्यादा गर्म होने, खराब क्वालिटी या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये बैटरियां आग पकड़ सकती हैं. खासतौर पर तब खतरा और बढ़ जाता है जब पावर बैंक को चेक-इन बैग या ओवरहेड बिन में रख दिया जाता है क्योंकि वहां उस पर तुरंत नजर रखना संभव नहीं होता.नियमों के अनुसार, यात्री पावर बैंक और अतिरिक्त लिथियम बैटरियां केवल हैंड बैगेज में ही ले जा सकते हैं. चेक-इन बैग में रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन यात्री इसको लेकर अकसर गलती करते नजर आ रहे हैं. DGCA ने यह भी स्पष्ट किया है कि पावर बैंक को ओवरहेड बिन में रखने से बचना चाहिए और उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां यात्री खुद उस पर नजर रख सके. इसका मकसद यह है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

अगर पावर बैंक से निकले धुआं तो क्या करें?

DGCA के सर्कुलर में यह भी साफ लिखा है कि फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का इस्तेमाल करना या उससे मोबाइल चार्ज करना मना है. इसके बावजूद कई यात्री उड़ान के समय मोबाइल चार्ज करते नजर आते हैं जो नियमों का उल्लंघन है और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी. अगर पावर बैंक या किसी डिवाइस से ज्यादा गर्मी महसूस हो, धुआं निकले या अजीब गंध आए तो यात्रियों को तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

भारत कर रहा पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी

पीएम मोदी ने दुनिया को बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली। भारत 2026 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी पूरी मजबूती से कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह एलान किया. पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले साढ़े 11 सालों में सरकार ने देश में खेलों के क्षेत्र में व्यापक बदलाव करते हुए 20 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए हैं. साथ ही भारत 'पूरी मजबूती से' 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है.

वाराणसी में आज से शुरू हुई 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में कई शहरों में फीफा अंडर-17 विश्व कप और हॉकी विश्व कप समेत 20 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं. उन्होंने कहा, "2030 के राष्ट्रमंडल खेल भी भारत में ही होने जा रहे हैं. भारत पूरी मजबूती से 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है. इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने के अधिक से अधिक मौके मिलें."

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार है. देश का हर क्षेत्र, विकास की हर परिभाषा इस 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' से जुड़ रहा है और खेलों की परिभाषा भी इसमें से एक है. उन्होंने कहा, "खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े व्यापक सुधार किये हैं. राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025... इस प्रकार के प्रावधानों से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा, खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही देश के युवाओं को खेल और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. एक तरफ हम अच्छा मूलभूत ढांचा और वित्त पोषण का तंत्र तैयार कर रहे हैं और उसके साथ ही नौजवानों को शानदार अनुभव देने के लिए भी काम कर रहे हैं."

मोदी ने कहा कि एक समय था जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का माहौल था. बहुत कम युवा खेल को करियर की तरह अपनाते थे लेकिन बीते दशक में खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है. प्रधानमंत्री ने खेलों के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा, "हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक का अनुभव देने में जुटे हैं. खेलो इंडिया अभियान की वजह से सैकड़ो युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे आने का मौका मिल रहा है. अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी आयोजन हुआ है. इसमें भी करीब एक करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई. सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब तीन लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया. मोदी ने कहा कि वाराणसी में अलग-अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं. नये खेल परिसर में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि काशी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो रही है। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए देश के खेल नक्शे पर जगह बनाना भी काशी के लिए बहुत अहम है."

बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया?

नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे के शेड्यूल का एलान कर चुका है. बांग्लादेश में टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. BCB के अनुसार, भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी. बांग्लादेश में भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. हालांकि, भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनयिक संबंधों के कारण भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है. बीसीबी द्वारा शेड्यूल की घोषणा करने के बावजूद भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरे पर जाना मुश्किल है.

बीसीबी ने शुक्रवार को भारत के बांग्लादेश दौरे का एलान किया था. बांग्लादेश बोर्ड ने दावा किया था कि बीसीसीआई से उनकी बात हो गई है. बीसीबी ने वनडे और टी20 सीरीज के मैचों की तारीख का भी एलान किया. शेड्यूल के मुताबिक, भारतीय टीम बांग्लादेश में 1, 3 और 6 सितंबर को तीन वनडे मैच खेलेगी. फिर 9, 12 और 13 सितंबर को तीन टी20 मैच खेले जाएंगे. यह सीरीज मूल रूप से पिछले साल आयोजित होने वाली थी, लेकिन भारतीय बोर्ड की सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया था. विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि बीसीसीआई इस बार भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका एक बड़ा संकेत आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश देना है. बांग्लादेश पिछले छह महीने से राजनीतिक हिंसा की चपेट में है और बीसीसीआई इस अस्थिरता की स्थिति में इस देश के दौरे का जोखिम नहीं लेना चाहता है. बीसीसीआई के निर्देशों पर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद बीसीबी का इस पर रुख सबकी नजरों में रहेगा. भारत और पाकिस्तान अपने सभी आईसीसी मैच तटस्थ मैदानों पर खेलते हैं, क्योंकि पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके संबंध और भी खराब हो गए हैं।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से फिर बढ़ेंगी सोने की कीमत

नई दिल्ली। देश में सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग पहले से ही परेशान हैं. ऊपर से अब वेनेजुएला में

अमेरिकी हमलों के बाद जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका असर आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ने की उम्मीद है. बीते 3 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है और जब तक वहां स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक इसे अमेरिका ही चलाएगा. इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भी अपने कब्जे में ले लिया है. इधर, वेनेजुएला के कुछ बड़े सहयोगी देश जैसे कि रूस, क्यूबा और ईरान ने वहां पर इन अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और इस कदम को उनकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।

क्रेडिट कार्ड यूजर की हो जाए मौत तो कौन चुकाएगा बकाया रकम?

नई दिल्ली। आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. लोगों की जेबों में रखी वॉलेट में आपको दो से तीन क्रेडिट क्रेडिट कार्ड तो मिल ही जाएंगे. क्रेडिट कार्ड इसलिए भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि यह तेजी से एडवांस्ड फंड पाने का एक आसान जरिया है.

HDFC बैंक, SBI और ICICI बैंक जैसे टॉप लेंडर अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया करा रहे हैं. इनके लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस डिजिटल और आसान है. आमतौर पर बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट उधार लेने वाले की इनकम और क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय करते हैं. क्रेडिट कार्ड के इसी बढ़ते इस्तेमाल के साथ क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कार्ड होल्डर की अचानक से मौत हो जाए, तो बकाए रकम का क्या होता है? कौन इसकी भरपाई करता है?

परिवार पर नहीं डाला जाता बोझ

आमतौर पर जब क्रेडिट कार्ड यूजर की मौत हो जाती है, तो बैंक उसकर प्रॉपर्टी या एसेट्स से बकाया वसूलने की कोशिश करता है. मान लीजिए अगर मृतक के नाम कोई पॉलिसी है या निवेश है या कोई प्रॉपर्टी उसके नाम है, तो बैंक कानूनी तरीके से इनसे अपना बकाया वसूल लेता है, लेकिन इनके न होने की स्थिति में उधार लेने वाले के परिवार पर कोई बोझ या दबाव नहीं डाला जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ कार्ड होल्डर की होती है. ऐसे में उसकी किसी परिस्थिति में मौत हो जाने पर कर्ज भी खत्म हो जाता है।

शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म?

नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया. शनिवार (03

जनवरी) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि 2026 की पहली सीरीज में शमी को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शमी का इग्नोर होना कहीं ना कहीं यह इशारा भी कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनसे आगे बढ़ चुका है और शायद यही शमी के इंटरनेशनल करियर की समाप्ति है. सोशल मीडिया पर भी शमी का चयन ना होने पर फैंस इमोशनल दिखाई दिए.शमी को टीम इंडिया में ना देखकर फैंस सोशल मीडिया पर काफी इमोशनल दिखाई दिए. एक यूजर ने शमी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आज के टीम सिलेक्शन से संकेत मिला कि मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का शायद यहीं अंत हो सकता है" इसी तरह भारतीय पेसर को लेकर फैंस काफी भावुक नजर आए.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 के अपने पहले ही मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. भारतीय अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच यूथ वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें वैभव कप्तान हैं. शनिवार को हुए पहले मुकाबले में वैभव बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, वह सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए. भारत अंडर-19 बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 पहला यूथ वनडे बेनोनी में खेला गया. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, कप्तान वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. आरोन जॉर्ज 5, वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू 21-21 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हरवंश पंगालिया ने 93 और आरएस अम्ब्रीश ने 65 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 300 पार पहुंचाया।

भारत में फास्ट-फूड नेटवर्क का विस्तार

केएफसी और पिज्जा हट का विलय

नई दिल्ली। केएफसी व पिज्जा हट ब्रांड के दो प्रमुख संचालक सफायर फूड्स इंडिया और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड (डीआईएल) का विलय होने जा रहा है। इससे 3,000 से अधिक 'स्टोर' वाला एक विशाल फास्ट-फूड नेटवर्क बनेगा। यम! ब्रांड्स के दो प्रमुख 'फ्रेंचाइजी' संचालकों देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड (डीआईएल) और सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड (एसएफआईएल) के निदेशक मंडलों ने बृहस्पतिवार को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में विलय के लिए एक व्यवस्था योजना को मंजूरी दी। इसका संयुक्त कारोबार करीब 8,000 करोड़ रुपये होगा।

समझौते की मुख्य बातें

समझौते के अनुसार, एसएफआईएल का विलय जयपुरिया परिवार द्वारा प्रवर्तित आरजी कोर्प की कंपनी डीआईएल में होगा। संयुक्त इकाई भारत, नाइजीरिया, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बाजारों में परिचालन करेगी। केएफसी, पिज्जा हट तथा टैको बेल जैसे यम! ब्रांड्स के अलावा संयुक्त इकाई को कोस्टा कॉफी, टी लाइव, न्यूयॉर्क फ्राइस और सानूक किचन जैसे अन्य वैश्विक क्यूएसआर ब्रांड के लाइसेंस भी उनके संबंधित बाजारों में प्राप्त होंगे।इसके अलावा, दो 'क्विक सर्विस रेस्टोरेंट' (क्यूएसआर) संचालकों के इस रणनीतिक एकीकरण से केएफसी और पिज्जा हट के लिए एक एकीकृत यम! इंडिया 'फ्रेंचाइजी' भी बनेगी। समझौते के अनुसार, एसएफआईएल के प्रत्येक 100 शेयर के बदले डीआईएल के 177 शेयर जारी किए जाएंगे।

हिस्सेदारी का रहेगा कुछ ऐसा पैटर्न

एसएफआईएल के संचालकों के पास वर्तमान में कंपनी में 25.35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें से डीआईएल की समूह कंपनी आर्कटिक इंटरनेशनल 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। डीआईएल ने कहा, " शेष हिस्सेदारी डीआईएल के शेयर में बदल दी जाएगी।" अमेरिका स्थित यम! ब्रांड्स ने डीआईएल और एसएफआईएल के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

170 दिन बाद चैतन्य की 'घर वापसी'

हाईकोर्ट की 'चुनिंदा कार्रवाई' पर टिप्पणी ने बढ़ाई जांच एजेंसियों की मुश्किलें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शनिवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई को बघेल परिवार और कांग्रेस समर्थकों ने 'सत्य की जीत' करार दिया है। हालांकि, इस रिहाई से ज्यादा चर्चा हाईकोर्ट द्वारा राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर की गई तीखी टिप्पणियों की हो रही है।

1. 'चुनिंदा कार्रवाई' (Selective Action) पर हाईकोर्ट का हथौड़ा

चैतन्य बघेल को जमानत देते समय हाईकोर्ट ने जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने सह-आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के मामले का जिक्र करते हुए पुलिस को फटकार लगाई:

फरार होने का मौका: कोर्ट ने हैरानी जताई कि जिस आरोपी के खिलाफ परमानेंट वारंट था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय केवल बयान लेकर जाने दिया, जिसके बाद वह फरार हो गया।

सख्त आदेश: कोर्ट ने इसे कानून का गंभीर उल्लंघन मानते हुए DGP को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के निर्देश दिए हैं।

2. बघेल परिवार का पलटवार: "बदले की राजनीति उजागर"

जेल से बाहर निकलते ही चैतन्य बघेल और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों (ED/EOW) पर तीखे हमले किए:

भूपेश बघेल: "जिस तरह ED और IT का दुरुपयोग किया गया, वह अब सबके सामने है। यह गिरफ्तारी केवल राजनीतिक द्वेष और साजिश का हिस्सा थी।"

चैतन्य बघेल: "मेरे बेटे के जन्मदिन पर मुझे रिहा किया गया, जबकि एजेंसियों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिरफ्तार कर खुशी छीनने की कोशिश की थी।"

3. क्या था घोटाले का 'थ्री-लेयर' मॉडल? (A, B, C कैटेगरी)

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस सिंडिकेट ने सरकारी खजाने को लूटने के लिए तीन तरीके अपनाए थे:

कमीशन (Part A): डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी ₹75 से ₹100 तक की अवैध वसूली।

नकली होलोग्राम (Part B): बिना टैक्स चुकाए नकली होलोग्राम वाली 40 लाख से ज्यादा शराब पेटियां सरकारी दुकानों से बेची गईं।

जोन आवंटन (Part C): डिस्टलरीज के सप्लाई एरिया को मनमाने ढंग से बदलकर ₹52 करोड़ की अवैध उगाही।

4. राजनीतिक निहितार्थ

चैतन्य बघेल की रिहाई छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। हाईकोर्ट द्वारा 'कानून के चुनिंदा इस्तेमाल' की टिप्पणी ने विपक्ष (कांग्रेस) को एक बड़ा हथियार दे दिया है। अब आने वाले समय में बघेल सरकार के कार्यकाल के अन्य मामलों में भी जांच की निष्पक्षता पर बहस छिड़ना तय है।

कानूनी नजरिया: हाईकोर्ट की सख्ती और पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिए गए निर्देश यह संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों को केवल बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि पुख्ता फॉरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों के साथ कोर्ट में खड़ा होना होगा।

भूपेश बघेल के सरगुजा दौरे से कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान उजागर

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से चली आ रही गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरगुजा दौरे के बाद स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की आंतरिक असहजता खुलकर दिखाई दी। दौरे के तुरंत बाद कुछ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर समन्वय की कमी अब संगठनात्मक अनुशासन को प्रभावित करने लगी है। यह दौरा भूपेश बघेल का सत्ता से बाहर होने के बाद सरगुजा क्षेत्र का पहला राजनीतिक प्रवास था। अंबिकापुर में उनके कार्यक्रमों के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक किसी औपचारिक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल नहीं दिखे। न तो संगठित स्वागत हुआ और न ही दोनों गुटों की साझा उपस्थिति सामने आई। दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने कुछ वरिष्ठ और युवा कांग्रेस नेताओं के निजी निवासों पर मुलाकात की। इसे राजनीतिक शिष्टाचार और व्यक्तिगत संबंधों के निर्वहन के रूप में देखा गया, लेकिन पार्टी के भीतर इसका अलग संदेश गया।

व्हाट्सएप ग्रुप विवाद बना चर्चा

दौरे के बाद "सरगुजा महाराजा की कांग्रेस" नामक एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं को हटाए जाने की सूचना सामने आई। ये वे लोग थे, जो भूपेश बघेल के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। हालांकि यह ग्रुप जिला कांग्रेस का आधिकारिक मंच नहीं है।

प्रियंका को असम, टीएस को तमिलनाडु-पुडुचेरी का जिम्मा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुडुचेरी से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ सप्तगिरि उलाका, इमरान मसूद और श्रीवेला प्रसाद को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में केरल के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में सैयद नासिर हुसैन, नीरज डांगी और अभिषेक दत्त को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुडुचेरी से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यशोमती ठाकुर, जी सी चंद्रशेखर और अनिल कुमार यादव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

भूपेश बघेल की टिप्पणी से साहू समाज आक्रोशित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाज़ी और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच टकराव सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर की गई छत्तीसगढ़ी टिप्पणी को लेकर साहू समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समाज का कहना है कि यह बयान केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है।

बिलासपुर के लिंगियाडीह क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी कहावत और प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से उपमुख्यमंत्री अरुण साव की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कथात्मक अंदाज़ में प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगाया, लेकिन इसी दौरान प्रयुक्त शब्दावली को साहू समाज ने अपमानजनक करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही तीखी राजनीतिक बहस का हिस्सा था, लेकिन इसकी भाषा ने विवाद को राजनीतिक दायरे से बाहर सामाजिक स्तर तक पहुंचा दिया। साहू समाज के प्रदेशाध्यक्ष नीरेन्द्र साहू ने इसे समाज के स्वाभिमान से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि यदि 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

हिंदू सम्मेलन के बाद अब युवा सम्मेलन

शताब्दी वर्ष पर आरएसएस 221 जगहों पर करेगा आयोजन

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है। इसके लिए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। सबसे अहम हिंदू सम्मेलनों का आयोजन है। राजधानी रायपुर में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन किया गया। इसमें आरएसएस के प्रमुख डा. मोहन भागवत आए थे। हिंदू सम्मेलन लगातार आरएसएस के मंडलों और शहर की बस्तियों में चल रहे हैं। ये सम्मेलन मकर संक्रांति तक चलेंगे। इसी के साथ इस माह अब युवा सम्मेलनों का भी आगाज होगा। ये सम्मेलन प्रदेश के 221 स्थानों में होंगे। इसका आगाज कब से होगा, इसका फैसला 10 जनवरी को दुर्ग में होने प्रांत की बैठक में होगा। आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष में साल भर के लिए कार्यक्रम तय किए हैं। इसका आगाज विजयादशमी से किया गया। विजयादशमी पर आरएसएस हमेशा से पथ संचलन का आयोजन करता है। इस बार दो अक्टूबर को विजयादशमी से लेकर 15 अक्टूबर तक प्रदेश में दो हजार स्थानों पर पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद नवंबर में घर-घर संपर्क अभियान चलाया गया। प्रदेश के हर गांव के हिंदू परिवारों के घरों तक स्वयंसेवक गए और उनको आरएसएस के सौ सालों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को संघ का साहित्य भी वितरित किया गया।

युवा सम्मेलन और गोष्टी

कार्यक्रमों की कड़ी में जनवरी में युवाओं के लिए युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 221 स्थानों पर होगा। इसमें 152 खंड और 69 नगर शामिल हैं। इसमें युवाओं की समस्याओं को भी जानने के साथ उनका निदान कैसे हो इस पर भी चर्चा होगी। युवाओं को पंच परिवर्तन के बारे में ठीक उसी तरह से बताया जाएगा, जिस तरह से राजधानी रायपुर के युवा संवाद में डा. मोहन भागवत ने बताया था। इसके अलावा मार्च में एक अलग तरह का आयोजन प्रमुख जन गोष्ठी होगी। इसमें अलग-अलग वर्गों के प्रमुख शामिल होंगे। जैसे ऑटो, ट्रक, टैक्सी के वाहन चालक। किसान, वकील, व्यापारी इनके प्रमुखों को बुलाकर एक मंच दिया जाएगा। सभी में राष्ट्रीयता और समाज को संगठित करने की भावना जगाने का काम होगा।

मकर संक्रांति तक हिंदू सम्मेलन

आरएसएस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ही देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में आरएसएस के 1601 मंडल हैं। ये मंडल प्रदेश के 19 हजार से ज्यादा गांवों को मिलाकर बनाए गए हैं। एक मंडल में आठ से दस गांवों का रखा गया है। अब हर मंडल में हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं।

बस्तर में 'नेटवर्क क्रांति'

माओवाद के खात्मे के साथ अब 500 गांवों में गूंजेगी डिजिटल दस्तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अंचलों से जैसे-जैसे हिंसा का साया हट रहा है, वैसे-वैसे विकास की नई किरणें वहां पहुंच रही हैं। राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने बस्तर और सरगुजा जैसे दुर्गम क्षेत्रों को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। केंद्र सरकार से 5,000 नए मोबाइल टावरों की मांग इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

'बुलेट' की जगह अब 'ब्रॉडबैंड' की बारी

केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को माओवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की रणनीति साफ है: जहां कल तक मुठभेड़ की खबरें आती थीं, वहां अब ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन शिक्षा पहुंचेगी। 'नियद नेल्ला नार' (आपका अच्छा गांव) योजना के तहत उन 500 गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो अब तक संचार के नक्शे से गायब थे।

डिजिटल कनेक्टिविटी: सुशासन का नया हथियार

राज्य में वर्तमान में लगभग 1,000 गांव 'डार्क जोन' (बिना नेटवर्क) में हैं। नेटवर्क न होने का सीधा असर सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर पड़ता है।

- **ई-ऑफिस और ऑनलाइन सेवाएं:** नेटवर्क आने से ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और बैंकिंग सेवाओं के लिए मीलों दूर नहीं जाना होगा।
- **स्वास्थ्य और आपातकाल:** भरतपुर-सोनहत और कांकेर के दबेना जैसे गांवों में एंबुलेंस बुलाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, वह अब बीते दिनों की बात होगी।

वर्तमान स्थिति,आगामी लक्ष्य / प्रस्ताव

- 671 टावर अब तक स्थापित,"5,000 नए टावरों का प्रस्ताव (डिजिटल भारत निधि से)"
- 365 टावरों पर 4G लाइव,513 नए 4G टावरों को हाल ही में मिली मंजूरी
- 728 टावर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सक्रिय,"1,000 'नो-नेटवर्क' गांवों को कवर करने की योजना"

4G से 5G की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

एक तरफ जहां सुदूर बस्तर में 4G के जरिए बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के शहरी केंद्रों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई) में 5G सेवाओं का विस्तार युद्ध स्तर पर जारी है। जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन-आइडिया (Vi) भी राज्य में अपनी 5G सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जो राज्य के 'डिजिटल डिवाइड' (शहरी और ग्रामीण अंतर) को कम करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना: पारदर्शिता की गारंटी

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डिजिटलीकरण को बजट में प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य केवल कॉल करना नहीं, बल्कि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करना और सुदूर आदिवासियों तक उनके हक का पैसा सीधे मोबाइल के जरिए पहुंचाना है।

यह केवल तकनीकी विस्तार नहीं है, बल्कि यह उन इलाकों में 'लोकतंत्र की वापसी' का प्रतीक है, जहां दशकों तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा हुआ था। जब एक आदिवासी युवा के हाथ में 4G/5G नेटवर्क होगा, तो वह केवल उपभोक्ता नहीं बनेगा, बल्कि सूचनाओं के जरिए सशक्त नागरिक बनेगा।

राष्ट्रपति और केंद्रीय गृहमंत्री करेंगे बस्तर पंडुम में शिरकत

अलग-अलग देशों में कार्यरत भारत के राजदूत आएंगे बस्तर

रायपुर। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला, लोकपरंपराओं और विरासत के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन इस साल भी किया जा रहा है। कार्यक्रम 10 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रस्तावित है। बस्तर पंडुम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे।

दरअसल, बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत बस्तर संभाग में 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 29 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम और 2 से 6 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संभाग स्तरीय कार्यक्रम में ही राष्ट्रपति और गृहमंत्री शिरकत करेंगे। इस बार के बस्तर पंडुम में विशेष रूप से भारत के अलग-अलग देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों को आमंत्रित किए जाने पर भी चर्चा हुई, ताकि उन्हें बस्तर की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और जनजातीय जीवन से अवगत कराया जा सके। इस साल बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जा रही है। जिन विधाओं में प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं होंगी, उनमें बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, पूजा-पद्धति, शिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन-औषधि प्रमुख हैं।

सीएम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात 'बस्तर पंडुम' में किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव 'बस्तर पंडुम 2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा, बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी में बस्तर में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिम नबीन से भेंट कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी। प्रदेश प्रभारी के रूप में उनके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और सतत परिश्रम ने छत्तीसगढ़ को संगठनात्मक दृष्टि से नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय उनके प्रेरक नेतृत्व का साक्षात परिणाम है। हमे पूर्ण विश्वास है कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊँचाइयों को स्पर्श करेगी और राष्ट्र सेवा के पथ पर और अधिक सशक्त बनेगी। पुनः बधाई। हार्दिक शुभकामनाएँ।

अस्पताल के गलियारों में अब नहीं कटेगी रातें

छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे हाईटेक 'आश्रय'

रायपुर। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले गरीब परिवारों के लिए अब 'मरीज' से ज्यादा उसकी 'तीमारदारी' की चिंता कम होगी। अक्सर देखा जाता है कि वार्ड में मरीज का इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसके परिजन अस्पताल की सीढ़ियों या खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर होते हैं। इस पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने 'सेवादान आरोग्य फाउंडेशन' के साथ एक ऐतिहासिक समझौता (MoU) किया है।

'नो प्रॉफिट-नो लॉस' मॉडल

यह परियोजना केवल ईंट-पत्थरों का निर्माण नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पताल में कॉर्पोरेट स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है। विश्राम गृहों का संचालन 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' के आधार पर होगा, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रथम चरण: इन चार शहरों को मिलेगी सौगात

योजना के शुरुआती चरण में राज्य के चार प्रमुख चिकित्सा केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जहां मरीजों का दबाव सबसे अधिक रहता है:

रायपुर: राजधानी होने के कारण प्रदेशभर के गंभीर मरीज यहाँ आते हैं।

अंबिकापुर: सरगुजा संभाग का मुख्य केंद्र।

जगदलपुर: बस्तर अंचल के आदिवासियों के लिए बड़ी राहत।

रायगढ़: औद्योगिक और ग्रामीण आबादी का संगम।

सुविधा

सुरक्षा : 24 घंटे सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी (CCTV) की निगरानी

भोजन : स्वच्छ और पौष्टिक आहार की उपलब्धता

वातावरण : "साफ-सुथरे बिस्तर, शौचालय और सम्मानजनक आवास"

संचालन : निर्माण से लेकर रखरखाव तक का जिम्मा 'सेवादान आरोग्य फाउंडेशन' का

इलाज में 'सुकून' की भूमिका

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार, इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि अपनों के साथ और सुकून से भी होता है। जब मरीज का परिजन तनावमुक्त और सुरक्षित रहेगा, तो वह मरीज की बेहतर देखभाल कर सकेगा। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ 'मानवता और संवेदना' के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

खजाने पर बिना बोझ के बड़ी सुविधा

इस मॉडल की खूबी यह है कि विश्राम गृहों के निर्माण, सजावट और दैनिक संचालन का पूरा आर्थिक जिम्मा संस्था उठाएगी। इससे राज्य सरकार के बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना जनता को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकारी अस्पतालों में 'अटेंडेंट' सबसे उपेक्षित वर्ग होता है। मुख्यमंत्री की यह पहल 'अंत्योदय' के विचार को पुख्ता करती है, जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है।

2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल

बॉलीवुड में पुराने और भरोसेमंद फॉर्मूले हमेशा काम करते हैं. सफल एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियां एक बार फिर लोगों के लिए बड़े परदे पर धमाका करने को तैयार हैं. 2026 में कई ऐसी जोड़ी अपनी केमिस्ट्री और अनुभव के साथ नई फिल्मों में वापसी कर रही हैं. चाहे कॉमेडी हो, एक्शन या रोमांस ये जोड़ियां पहले ही अपने काम से लोगों का दिल जीत चुकी हैं और अब उनकी नई फिल्में भी इसी जादू को दोहराने का वादा करती हैं.

अनुराग सिंह पहले भी पंजाबी फिल्मों पंजाब 1984 (2014) और सुपर सिंह (2017) में दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ काम कर चुके हैं. अब ये जोड़ी हिंदी फिल्म बॉर्डर 2 में फिर से साथ नजर आएगी. ये फिल्म गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर रिलीज होगी. अनुराग सिंह पहले भी पंजाबी फिल्मों पंजाब 1984 (2014) और सुपर सिंह (2017) में दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ काम कर चुके हैं. अब ये जोड़ी हिंदी फिल्म बॉर्डर 2 में फिर से साथ नजर आएगी. ये फिल्म गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर रिलीज होगी.

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर ने 2009 में कमीने से धमाका किया था. इसके बाद हैदर (2014) और रंगून (2017) में भी दोनों ने शानदार काम किया. अब दोनों फिर से एक्शन फिल्म ओ'रोमियो में साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में त्रिप्ती दीमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी भी हैं. फिल्म फरवरी में रिलीज होगी. विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर ने 2009 में कमीने से धमाका किया था. इसके बाद हैदर (2014) और रंगून (2017) में भी दोनों ने शानदार काम किया. अब दोनों फिर से एक्शन फिल्म ओ'रोमियो में साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में त्रिप्ती दीमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी भी हैं. फिल्म फरवरी में रिलीज होगी.

इस साल होगा शाहिद का राज

साल 2026 बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर के नाम होने वाला है. इस साल उनकी दो शानदार फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. पहले उनकी रोमांटिक फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी और अब उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' की भी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. ये दोनों फिल्में 2026 में ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं.शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इश्क फरमाती दिखाई देंगी. 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन डे के मौके पर 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं शाहिद की दूसरी फिल्म 'कॉकटेल 2' 'ओ रोमियो' की रिलीज के 6 महीने बाद, सितंबर 2026 में बड़े पर्दे पर आएगी.'ओ रोमियो' और 'कॉकटेल 2' की रिलीज के बीच गैप को लेकर मिड डे ने सूत्र के हवाले से लिखा- 'ये गैप सोच-समझकर तय किया गया था. ओ रोमियो और 'कॉकटेल 2' बिल्कुल अलग फिल्में हैं, और कोई नहीं चाहता था कि वो एक-दूसरे के रास्ते में रुकावट बनें. छह महीने का समय शाहिद को नई एनर्जी और इमेज के साथ आने का मौका देता है. कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है. दर्शकों को एक किरदार से आगे बढ़ने और दूसरे को अपनाने के लिए समय चाहिए होता है. सितंबर में रिलीज होने से कॉकटेल 2 को अपनी अलग पहचान मिलेगी."कॉकटेल 2' को लेकर रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'कहानी के लिहाज से फिल्म लगभग तैयार है।

आलिया ने शेयर की क्यूट फैमिली पिकनिक फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग फिल्मों को लेकर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में उन्होंने आज अपने फैंस के लिए एक खास तोहफा दिया. आलिया ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसे उन्होंने 2026 के वेलकम के कैप्शन के साथ पोस्ट किया है. इस तस्वीर में आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा भी नजर आ रहे हैं. तस्वीर में ये तीनों मिलकर नए साल की खुशियों को एन्जॉय करते दिख रहे हैं और फैमिली वाइब्स फैंस को खूब भा रही हैं. 4 जनवरी 2026 को आलिया भट्ट ने साल की पहली फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने पति और बेटी के साथ मस्ती करती हुई दिख रही हैं. तस्वीर में रणबीर कपूर अपनी बेटी को हवा में उछाल रहे हैं और आलिया लाडली को देख मुस्कुराती हुई दिख रही हैं. समंदर के किनारे, सनसेट के बीच आलिया, रणबीर और राहा की ये फोटो फैंस का दिल जीत रही है. इस पोस्ट के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा- 'आगे बढ़ते रहो प्यारे....' आलिया जल्द ही फिल्म 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी. 'अल्फा' एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी नजर आएंगे।

माही विज-जय भानुशाली 15 साल बाद हुए अलग

टीवी के पॉपुलर कपल माही विज और जय भानुशाली ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. उन्होंने अपनी 15 साल की शादी तोड़ दी है. जय और माही ने सोशल मीडिया पर सेपरेशन की खबरों को लेकर पोस्ट शेयर की है. माही और जय ने बताया कि उनकी इस कहानी में कोई भी विलेन नहीं है. जय और माही ने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'आज हम इस सफ़र में अलग होने का फैसला करते हैं, जिसे जिंदगी कहते हैं. फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे. शांति, ग्रोथ, दयालु और इंसानियत हमेशा हमें सिखाते रहेंगे. हमारे बच्चे तारा, खुशी और राजवीर के लिए हम बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे. और वो सबकुछ करेंगे जो बच्चों के लिए जरुरी होगा.'आगे उन्होंने लिखा, 'हम अलग-अलग रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हमारी इस कहानी का कोई विलेन नहीं है. इस निर्णय के साथ कोई भी निगेटिविटी नहीं है. कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कृपया जान लें कि हम ड्रामा से ज्यादा शांति और सबसे ऊपर समझदारी को चुनते हैं. हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहेंगे. एक दूसर का सपोर्ट करते रहेंगे और हमेशा दोस्त रहेंगे. हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों से रिस्पेक्ट, प्यार मांगते हैं.' बता दें कि जय और माही ने 2010 में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी. कपल 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं. दो बच्चे खुशी और राजवीर के वो फोस्टर पेरेंट्स हैं. वहीं 2019 में वो बेटी तारा के पेरेंट्स बने।

ऐतिहासिक क्लब में एंट्री लेने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म

'धुरंधर' की कमाई 800 करोड़ पार

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब पूरा एक महीना हो गया है. लेकिन एक महीने बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ती नहीं दिख रही है. दर्शक 'धुरंधर' को एक बार नहीं, बल्कि बार-बार देखने थिएटर्स जा रहे हैं और ऐसे में फिल्म अब 800 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है. वहीं 31वें दिन के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2: द रूल' के हिंदी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तहस-नहस कर दिया है.

धुरंधर के रिकार्ड

- 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते 218 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- दूसरे हफ्ते 261.5 करोड़ और तीसरे हफ्ते 189.3 करोड़ रुपए की कमाई की.
- 'धुरंधर' के चौथे हफ्ते का कलेक्शन 115.70 करोड़ रुपए रहा और अब 5वें हफ्ते भी ये धांसू कमाई कर रही है.
- रणवीर सिंह की फिल्म ने 29वें दिन 9.70 करोड़ और 30वें दिन 12.60 करोड़ रुपए कमा लिए थे.
- 30 दिन में 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 806.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया.
- इसी के साथ 'धुरंधर' भारत में 800 करोड़ का हिस्सा बनने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ा

'धुरंधर' 31वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक (शाम 6 बजे) 10.07 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 817.50 करोड़ रुपए हो गया है.

इसी के साथ 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. अल्लू अर्जुन स्टारर ये फिल्म 812 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी. लेकिन अब ये खिताब 'धुरंधर' ने अपने नाम कर लिया है. वर्कफ्रंट पर अब रणवीर सिंह 'प्रलय' में नजर आएंगे. इस फिल्म को जय मेहता बना रहे हैं जिसमें एक्टर के साथ कल्याणी प्रियदर्शन दिखाई दे सकती हैं. इसके अलावा 16 जनवरी 2026 को रणवीर की डेब्यू फिल्म 'बैंड बाजा बारात' भी सिनेमाघरों में री-रिलीज हो रही है.

छत्तीसगढ़ अंचल में काष्ठ शिल्प और चित्रकला

डा. सुशील त्रिवेदी

छत्तीसगढ़ अंचल में काष्ठ शिल्प और चित्रकला अत्यंत समृद्ध है जिसमें बस्तर में लकड़ी का जितना पारंपरिक उत्कृष्ट कलात्मक कार्य होता है उतना प्रदेश के किसी अन्य अंचल में नहीं पाया जाता। यहां के आदिवासी मकान, घोटुल-गुड़ी, खम्भ, तीर धनुष आदि बनाने में दक्ष हैं। बस्तर की सकल नारायण की गुफा के काष्ठ स्तंभ में शिवलिंग और हनुमान उत्कीर्ण हैं। आदिम मूर्ति कला और देवी स्तंभ काष्ठ आधारित हैं। यहां के आंगादेव, पाटदेव, डोकर डोकरी, माता झूला, हिंगलाजिन, बंजारिन, भीमा देव आदि की मूर्तियां आदि काल से काष्ठ निर्मित रही हैं। रायगढ़ और सरगुजा में लकड़ी से बनाए जाने वाले शिल्प अपने आकार प्रकार में बस्तर के काष्ठ शिल्प से भिन्न होते हैं। यहां मृतक स्तंभ भी काष्ठ निर्मित होते हैं जिसमें अदभुत चित्रकारी होते हैं। बस्तर दशहरा में रथ के निर्माण भी काष्ठ कला का उदाहरण है। सरगुजा के मूर्ति शिल्प में शिव, करम देव, नाग देव, टांगी नाथ देव, मोती बरहिया, विष्णु वाहन, गरुड़ आदि मूर्तियां भी काष्ठ निर्मित होती हैं। सरगुजा के पंडो, कंवर आदि के स्तंभों में गंगा जमुना का प्रतीकात्मक चित्रण होता है।

रामनामी मेले का आयोजन

प्रो अश्विनी केशरवानी

रामनामी पंथ का द्वितीय मेला पौष एकादशी से त्रयोदशी तक आयोजित किया जाता है। मेला में सामाजिक वाद विवादों, पारिवारिक झगड़ों का फैसला होता है। इसके अलावा महासभा का आयोजन और सामूहिक विवाह भी होते हैं। अगला मेला किस स्थान पर लगेगा, इसका निर्णय भी हो जाता है। यह मेला महानदी के तटवर्ती ग्रामों में एक बार उत्तर में तो दूसरी बार दक्षिण दिशा में लगता है। आयोजन के पीछे मान्यता है कि बहुत पहले सवारियों से भरी नाव मझधार में फंस गई। काफी प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता दिखा। तभी नाव में संयोग से रामनामी पंथ के प्रवर्तक परसराम भारद्वाज और उनके अनुयाई भी शामिल थे।

सबने उनसे भी मन्नतें मांगने का अनुरोध किया। उनके मन्नत मांगने पर नाव सकुशल किनारे लग गई। सभी का मन खुशी से भर गया, तभी से यहां मेले का आयोजन प्रति वर्ष नियत तिथि में होता आ रहा है।

गुदुम बाजा ल सिंग बाजा घलव केहे जाथे

टिकेश्वर सिन्हा' गब्दीवाला'

छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य में गुटुम बाजा के बड़ महत्तम हे। एला सींग बाजा घलव केहे जाथे। काबर की कोनो क्षेत्र विशेष में बाजा के सुघराई लाए बर लकड़ी या कोनो जीनिस के सींग असन लगाए जाथे। गुदुम ह घलो माटी के बिन बारा हड़िया या फेर लोहा के चद्दर के हड़ियानुमा खोल होथे, एमा चमड़ा छवाय रथे। आवाज में गद यानि मोटा सुर लाए बर अंडी तेल, रबर, लोभान, धूप जला के वोकर राख ल छेना राख में मिला के चमड़ा ऊपर लगाए जाथे। अऊ हड़िया के पाछु म नानुक छेद कर के जरुवत मुताबिक तेल डारे जाथे, जेकर ले सुर में मधुरता बने रथे। गुदुम बजाने वाला ह कनिहा में बांध के चार पहिया गाड़ी के टायर ले बने रबर के बठेना ले येला बजाथे। बिहातरा नेग, नृत्य मुद्रा आऊ गीत के बोल मुताबिक गुदुम ह बाजा ल हथेली य कोहनी म बजाथे। ये प्रमुख पारंपरिक बिहतरा बाजा आय जेकर ले सुर निकलथे।

कैबिनेट मिशन योजना और देशी रियासत

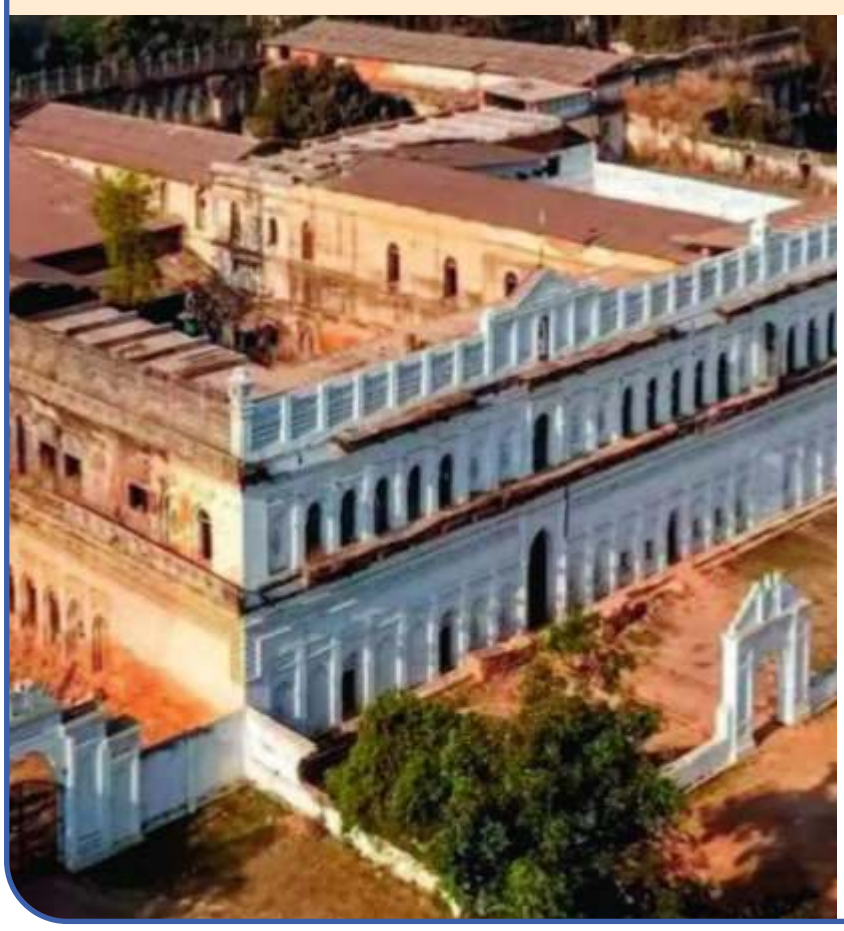

डा. अरविन्द शर्मा

माउंटबेटेन योजना में प्रस्तुत हस्तांतरण की योजना में भारत पाक विभाजन के साथ ही ब्रिटिश भारत में अब तक मिला लिए गए या साम्राज्ञी के अधीन विभिन्न देशी रियासतों को पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व या दर्जा प्राप्त किया गया था। सर्वोच्च सत्ता के निर्देश एवं नीति के आधार पर ब्रिटिश भारत की सरकार भीतर देशी रियासतों से संबंध बनाने में व्यस्त रही। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे देशी रियासत भी अंग्रेजों की इस नीति से संबंधित थी। इन देशी रियासतों के लिए एक लायजन आफिसर के पद व अधिकारों में वृद्धि कर उसे क्षेत्रीय आयुक्त का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों में संदर्भ में उप क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति हुई। इस समय छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थीं। कैबिनेट मिशन योजना तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के राजा एक अलग से देशी रियासतों का संघ बनाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों के प्रतिनिधि अपने पूरे तामझाम और लाव लश्कर के साथ रायपुर स्थित राजकुमार कालेज में एकत्र हुए और वहां उन्होंने पूर्वी रियासतों का संघ निर्मित किया, जो 1 अगस्त 1974 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इनमें दो बड़ी रियासत मयूरभंज और बस्तर प्रमुख थीं। इस संविधान के अनुसार संघ का एक अध्यक्ष, एक मुख्य सचिव और संयुक्त पुलिस संगठन जिसे ज्वाइंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था, निर्मित किया गया। यह पुलिस संगठन पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कार्य करता था। यह प्रारंभ में उपरोक्त दो बड़े राज्यों और बाद में एक अन्य सदस्य राज्यों के वित्तीय सहायता के आधार पर कार्य कर रहा था। संयुक्त पुलिस संगठन के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी भी नियुक्त की गई थी।

छत्तीसगढ़ी साहित्य में मौलिक उपन्यास का तृतीय क्रम

डा. मंजू शर्मा

छत्तीसगढ़ी के मौलिक उपन्यास के तृतीय क्रम में ठाकुर हृदय सिंह चौहान का फुटहा करम 1971 और पंडित कृष्ण कुमार शर्मा का छेरछेरा 1983 चतुर्थ उपन्यास है। दोनों में आंचलिकता, कथा, घटना और वातावरण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत है। फुटहा करम एक रानी की नियति की दुख भरी गाथा है। इसी भांति छेरछेरा सामंती सभ्यता में फंसे कृषक जीवन की व्यथा और विनोबा तथा गांधी जी की विचार धारा से ग्रामोदय की कथा आंचलिकता के साथ ग्रंथित है। केयूर भूषण कृत कुल के मरजाद 1995 छत्तीसगढ़ी का पंचम प्रकाशित मौलिक उपन्यास है जो जन चेतना प्रकाशन रायपुर की प्रस्तुति है। इसमें भी स्वतंत्रता पूर्व के रजवाड़ों का इतिहास एवं उनके विघटन का प्रकाश आंचलिक रूपों में विवेचित है। हेमनाथ यदु की चंदा चंदैनी, मैथ्यू जहानी कृत चंदा के डोंगा सुरुज के गांव और ठाकुर बलदेव सिंह चौहान कृत मानवता के कछेरी मा तथा हृदय सिंह चौहान कृत पठौनी और हाथ भर चूरी बीता भर पेट अप्रकाशित महत्वपूर्ण कृतियां हैं। डा जे आर सोनी कृत षष्ठ उपन्यास उढरिया 2000 आंचलिकता और छत्तीसगढ़ की गरिमा को लेकर सृजित पठनीय उपन्यास है।

साप्ताहिक शहरसत्ता

करोड़ों का 'वन भैंसा' घोटाला

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने 20 साल तक पाले 'हाइब्रिड' अब पोल खुली तो गुपचुप सीमा पार खदेड़ा

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 810982829

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु 'वन भैंसा' के संरक्षण के नाम पर दो दशकों से चल रहा एक बड़ा खेल बेनकाब हो गया है। जिस नस्ल को 'शुद्ध' बताकर वन विभाग वर्षों तक अपनी पीठ थपथपाता रहा और सरकारी खजाने से 2.46 करोड़ रुपये स्वाहा कर दिए, वे अंततः 'हाइब्रिड' (मिश्रित नस्ल) निकले। साक्ष्यों को मिटाने के लिए विभाग ने अब इन भैंसों को उदंती-सीता नदी टाइगर रिजर्व से 100 किलोमीटर दूर ओडिशा की सीमा में खदेड़ दिया है।

शुद्धता का ढोंग: दस्तावेजों में था सच, फाइलों में दबाया झूठ

वन्यजीव प्रेमियों का आरोप है कि विभाग को शुरू से ही पता था कि ये भैंसे शुद्ध नस्ल के नहीं हैं। 2007 में 'आशा' नामक मादा भैंस को शुद्ध बताकर लाया गया, लेकिन उसी समय खरीदी गई 'रंभा' और 'मेनका' के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से 'क्रॉस ब्रीड' दर्ज था।

धोखे का प्रचार

इसके बावजूद, विभाग ने सालों तक इन्हीं हाइब्रिड भैंसों से पैदा हुए बच्चों को राजकीय पशु के संरक्षण की 'बड़ी सफलता' के रूप में पेश किया।

कैसे खुली पोल? केंद्रीय प्राधिकरण की 'ना' ने बिगाड़ा खेल

इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ वन विभाग ने असम से लाए गए शुद्ध नस्ल के वन भैंसों के साथ इनका प्रजनन (Breeding) कराने का प्रस्ताव केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) को भेजा। प्राधिकरण ने तकनीकी जांच के बाद सख्त लहजे में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि हाइब्रिड भैंसों के साथ प्रजनन से शुद्ध नस्ल के भी दूषित होने का खतरा था।

'बाड़ा तोड़कर भागने' की संदिग्ध पटकथा

अक्टूबर 2023 में विभाग ने एक कहानी रची कि ये भैंसे बाड़ा तोड़कर भाग गए हैं। सच्चाई यह है कि जब हाइब्रिड होने की बात सार्वजनिक होने लगी, तो इन्हें ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। 10 दिन पहले इन्हें जानबूझकर ओडिशा की ओर खदेड़ा गया ताकि ये वापस न आ सकें। इस दौरान ग्रामीणों की फसलों का नुकसान हुआ, लेकिन विभाग अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है।

कालखंड,खर्च की गई राशि,स्थिति

2013-14 से 2024-25,"₹2,46,00,000","चारे, सुरक्षा और संरक्षण के नाम पर खर्च"
नतीजा,शून्य (0),राजकीय पशु की शुद्ध नस्ल बचाने में विफलता

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27